



लखनऊ से प्रकाशित एवं अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापूर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून गाजियाबाद , दिल्ली ,पंजाब , हरियाणा ,चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित

संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा, सभी विभागों3जल संकट का असंतुलित प्रबंधन अस्तित्व पर मंडराता4स्टारशिप ने 20 उन्नत स्टारलंक उपग्रहों के साथ भरी सफल उड़ान.....08

सीमा सड़क संगठन ने राजौरी पुंछ और रियासी में संपर्क मार्ग किया बहाल

पाकिस्तान में सत्ता का असली केन्द्र अब भी सेना, राजनीतिक संकट गहरा रहा: रिपोर्ट

श्रीनगर। लगातार भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू-कश्मीर के राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों में कई प्रमुख सड़कें बंद हो गई थी। ऐसे मुश्किल हालात में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने तेजी से कार्रवाई करते हुए प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क बहाल कर दिया, जिससे सुरक्षा बलों, राहत दलों, आवश्यक सेवाओं और स्थानीय लोगों की आवाजाही फिर से सामान्य हो सकी। 19 से 24 जुलाई के बीच हुई लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। इसके चलते कई अहम मार्ग मलबे से भर गए और लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीमा सड़क संगठन ने तुरंत अपने कमर्चरियों, भारी मशीनों और अन्य संसाधनों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा। खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सड़कों से मलबा हटाने का काम लगातार जारी रखा गया। सबसे अधिक असर राजौरी-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ा, जहां कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ। संगठन की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सड़कों से मलबा हटया, जिससे सुरक्षा बलों के वाहन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और स्थानीय लोगों की आवाजाही दोबारा शुरू हो सकी। रियासी से महोदर तथा राजौरी से बुबल, महोदर और गुल जाने वाले मार्गों पर भी कई जगह भूस्खलन हुआ। बड़ोरा नाले पर बनाया गया वैकल्पिक मार्ग तेज पानी



के बहाव में बह गया, लेकिन पहले से लगाए गए 200 फुट लंबे अस्थायी पुल के कारण यातायात पूरी तरह बंद नहीं हुआ और महोदर क्षेत्र का संपर्क बना रहा। संगठन ने बताया कि वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले संवेदनशील स्थानों को पहचान कर वहां आवश्यक संसाधन पहले ही पहुंचा दिए गए थे। इसी तैयारी के कारण सड़कों को कम समय में फिर से चालू किया जा सका। अग्रिम क्षेत्रों की सड़कों को भी प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया गया, ताकि सुरक्षा बलों की आवाजाही प्रभावित न हो। लगातार बारिश से सड़क निर्माण कार्य में लगी एजेंसियों के उपकरणों और अन्य ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसके बावजूद सीमा सड़क संगठन और निर्माण कार्य में लगी टीमों ने कठिन परिस्थितियों में लगातार काम

जारी रखा। उन्होंने सड़कों से मलबा हटया, कमजोर हिस्सों को सुरक्षित बनाया और कम समय में यातायात फिर से शुरू कर दिया। संगठन ने कहा कि सभी प्रमुख मार्गों पर आवश्यक संपर्क बहाल कर दिया गया है, लेकिन सड़कों को हुए नुकसान की मरम्मत का काम अभी भी जारी है। टीमें लगातार तैनात हैं, ताकि यातायात बिना किसी रुकावट के चलता रहे और लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सीमा सड़क संगठन ने कहा कि वह प्राकृतिक आपदाओं और कठिन परिस्थितियों में भी देश के सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने का अपना दायित्व पूरी निष्ठा से निभाता रहेगा। संगठन का उद्देश्य हर मौसम में सड़क संपर्क बनाए रखना और लोगों के साथ-साथ सुरक्षा बलों की आवाजाही को सुचारु बनाए रखना है।

पाकिस्तान में सत्ता केवल निर्वाचित सरकार के हाथों में नहीं है, बल्कि देश की राजनीतिक व्यवस्था एक ‘हाइब्रिड सिस्टम’ के तहत संचालित होती है, जिसमें सेना राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक राजनीति दोनों में निर्णायक भूमिका निभाती है। यह दावा राजनीतिक शोधकर्ता वास शेनॉय ने ‘द टाइम्स ऑफ इजरायल’ में प्रकाशित एक रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार को 2024 के आम चुनावों की निष्पक्षता पर उठे सवालों, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी एवं राजनीतिक अलगाव, मीडिया पर कथित प्रतिबंध, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कमी और देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों के कारण वैधता के संकट का सामना करना पड़ रहा है। जो हालात हैं उससे धारणा मजबूत हुई है कि चुनाव की महत्ता कम हो गई है। इन परिस्थितियों ने पाकिस्तान के लाखों नागरिकों के बीच यह धारणा मजबूत की है कि अब चुनाव के जरिए शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन संभव नहीं रह गया है। इसके चलते संवैधानिक राजनीति पर लोगों का भरोसा कमजोर



हुआ है और जनाक्रोश सीधे राज्य की संस्थाओं की ओर बढ़ रहा है। शेनॉय ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का सुरक्षा माहौल लगातार बिगड़ रहा है। उनके अनुसार, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने खासकर खैबर पख्तूनख्वा में अपने हमले तेज कर दिए हैं, जबकि बलूच अलगाववादी दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में सरकार को चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट-खुरासान (आईएस-के) और अन्य सांप्रदायिक संगठन भी सक्रिय हैं।रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान इन समूहों में से कुछ के लिए सुरक्षित ठिकाने का काम करता है, जबकि पाकिस्तान की आतंकवादी

संगठनों के प्रति अतीत की चयनात्मक नीति ने ‘उपयोगी’ और ‘शत्रुतापूर्ण’ माने जाने वाले संगठनों के बीच की रेखा धुंधली कर दी है। आर्थिक स्थिति पर दिष्णगी करते हुए शेनॉय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहायता से फिलहाल भुगतान संतुलन संकट का तत्काल खतरा टल गया है, लेकिन पाकिस्तान अब भी भारी कर्ज, सीमित कर आधार, ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय समस्याओं, कमजोर सार्वजनिक सेवाओं और विदेशी वित्तीय सहायता पर निर्भरता, जैसी संरचनात्मक चुनौतियों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबी, तेजी से बढ़ती आबादी और बाढ़, भीषण गर्मी तथा जल संकट जैसी समस्याएं देश की क्षमता को

और कमजोर कर रही हैं। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ आर्थिक और जलवायु सहयोग जारी रखना चाहिए, लेकिन साथ ही विश्वसनीय चुनाव, मजबूत नागरिक शासन और सभी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ समान कार्रवाई की स्पष्ट शर्तें भी रखनी चाहिए। शेनॉय ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को उसी तरह समर्थन देने से बचना चाहिए, जैसा अतीत में जनरल जिया-उल-हक को दिया गया था। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर भी ये रिपोर्ट अगाह करती है। शेनॉय के अनुसार, पाकिस्तान के परमाणु हथियार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और विशेष कमान एवं नियंत्रण प्रणाली के अधीन हैं तथा उनके उपवादी संगठनों के हाथ लगने की संभावना फिलहाल बेहद कम है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में अंदरूनी मिलीभगत से परमाणु सामग्री की चोरी, परमाणु ढांचे में तोड़फोड़, हथियारों के परिवहन पर हमले, संवेदनशील सामग्री के गायब होने या सैन्य तंत्र में विभाजन की स्थिति में नियंत्रण प्रणाली कमजोर पड़ने जैसे जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

सांक्षिप्त ख़बरें

यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ सारनाथ, 28 साल का इंतजार ख़त्म

वाराणसी। भगवान बुद्ध की प्रथम धर्मदेशना स्थली सारनाथ को आखिरकार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मिति के 48वें सत्र में शनिवार को इस ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की गई। करीब 28 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद मिली इस मान्यता के साथ सारनाथ भारत का 45वां और उत्तर प्रदेश का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। इस उपलब्धि से न केवल प्रदेश की समृद्ध बौद्ध विरासत को वैश्विक पहचान मिलेगी, बल्कि पूर्वांचल में धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। सारनाथ को 3 जुलाई 1998 को यूनेस्को की टेंटेटिव (संभावित) सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद विशेषज्ञों द्वारा लंबे समय तक मूल्यांकन और विभिन्न चरणों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इसे आधिकारिक रूप से विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल थे। सारनाथ के जुड़ने के साथ पहली बार पूर्वांचल का कोई स्थल इस प्रतिष्ठित सूची का हिस्सा बना है।

ग्वालियर के इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित मुरार आर्मी कैंट क्षेत्र के बंसीपुरा में शनिवार को एक निजी इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें और आसमान में उठते धुएँ के घने गुबार को दूर-दूर तक देखा गया, जिससे आसपास के इलाक़े में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम को दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग की भयावहता को देखते हुए अब तक 40 से 50 फायर ब्रिंड वाहनों को राहत एवं बचाव कार्य में लगाया गया है। गोदाम आर्मी कैंट क्षेत्र के समीप होने के कारण सेना के जवान भी आग बुकने और राहत कार्य में सहयोग कर रहे हैं। दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लपटें आसपास के गोदामों और अन्य प्रतिष्ठानों तक न फैल सकें। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोदाम में बड़ी मात्रा में टीवी, फ़िज़, ऐयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, अलमारियां, पानी की मोटर सहित अन्य महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखे हुए थे।

राष्ट्रपति ने मंजूर किया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार



नई दिल्ली(एजेंसी)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर शनिवार को प्रधान का इस्तीफा मंजूर करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को उनके वर्तमान मंत्रालयों के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। धर्मेन्द्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से प्रह्लाद जोशी को सौंपने का निर्णय लिया। प्रह्लाद जोशी

वर्तमान में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा तथा उपभोक्ता मामले मंत्रालयों का की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से प्रह्लाद जोशी को सौंपने का निर्णय लिया। प्रह्लाद जोशी

कामकाज में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुचारु रूप से जारी रहेंगी। इस्तीफा देने के बाद धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रसेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और आगे भी रहेगी। उनके आवास पर भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक

गठबंधन (एनडीए) के कई वरिष्ठ नेताओं का पहुंचना लगातार जारी रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी सहित भाजपा और एनडीए के

महिला को बचाने पहुंची यूपी-112 टीम पर हमला, पुलिसकर्मियों से मारपीट

बलरामपुर(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में पति-पत्नी के घरेलू विवाद की सूचना पर पहुंची यूपी-112 पुलिस टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस का आरोप है कि महिला को भीड़ से सुरक्षित निकालकर उसकी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करते ही कुछ लोगों ने पुलिस टीम को घेर लिया और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना में दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। राहगीरों और कुछ ग्रामीणों की मदद से पुलिसकर्मी किसी तरह मौके से निकलकर

अपनों जान बचा सके। घटना कांतवाली देहात क्षेत्र के खमौवा गांव की है। शुक्रवार शाम यूपी-112 कंट्रोल रूम पर नन्जो नामक महिला ने सूचना दी कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया है और उसकी बच्ची को अपने पास रखा हुआ है। सूचना मिलते ही पीआरवी-5038 पर तैनात आरक्षी दीपक कुमार राय और चालक आरक्षी मोहम्मद आरिफ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम जब गांव स्थित ईदगाह के पास पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र थे। महिला भीड़ के बीच घिरी हुई थी।

जौहर विवि दौरे के दौरान सपा में दिखी गुटबाजी, इकरा हसन और आजम समर्थकों में धक्का-मुक्का



रामपुर(एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के रामपुर दौरे के दौरान शनिवार को जौहर रोड स्थित संत शिरोमणि गेस्ट हाउस में उस समय अफरातफरी मच गई, जब सांसद इकरा हसन और वरिष्ठ सपा नेता आजम खां के समर्थक हॉल में प्रवेश की लेकर आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच पहले तीखी नोकझोंक मोहम्मद आरिफ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम जब गांव स्थित ईदगाह के पास पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र थे। महिला भीड़ के बीच घिरी हुई थी।

आजम खां के समर्थक भी बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद थे। सीमित स्थान और भारी भीड़ के कारण दोनों पक्षों के बीच कड़ासुनी शुरू हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति कुछ देर के लिए इतनी बिगड़ गई कि प्रवेश द्वार पर अव्यवस्था फैल गई और गेस्ट हाउस के हॉल में व्यवस्था की गई थी। बैठक शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भी हॉल के भीतर जाने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान सांसद इकरा हसन के समर्थकों ने उनके साथ प्रवेश करने की कोशिश की, जबकि

सामान्य होने के बाद प्रतिनिधिमंडल की बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू हुई। गौरतलब है कि दो दिन पहले भी समाजवादी पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के रामपुर दौरे के दौरान रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और आजम खां के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। उस दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की थी, जिससे पार्टी के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आई थी।

धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा नई पीढ़ी और इंकलाब की जीत: अखिलेश यादव

स्वतंत्र प्रभावत संवाददाता आज़मगढ़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे को नई पीढ़ी, छात्रों और युवाओं के आंदोलन की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के संघर्ष ने केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और यह लोकतांत्रिक आंदोलन को सफलता का प्रतीक है। शनिवार को आजमगढ़ में मोड़िया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक होने और इससे जुड़े घटनाक्रम के बाद सरकार को तुरंत जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी। उनका आरोप था कि सरकार ने लंबे समय तक मामले को संभालने की कोशिश की, जबकि छात्रों की मांगों पर समय रहते निर्णय लिया

जा सकता था। अखिलेश यादव ने कहा कि देश की नई पीढ़ी ने सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से अपने आंदोलन को गुच्छी स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि युवाओं की एकजुटता के कारण सरकार को अपना रुख बदलना पड़ा। उनके अनुसार, यह आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से युवाओं की आवाज को बुलंद करने का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पूरे घटनाक्रम से सबक लेते हुए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक न हो, इसके लिए पारदर्शी और मजबूत प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में छात्र-युवा संगठनों के साथ-साथ विपक्ष ने भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार उठाई थी।



संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा, सभी विभागों को समन्वय से काम करने के निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शनिवार को अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान की प्रगति, विभिन्न विभागों की गतिविधियों तथा जनपदों में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों का विस्तृत आकलन किया गया। अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि जनपदों में स्वच्छता अभियान को गति देते हुए नालियों की नियमित सफाई, जलभराव की रोकथाम, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा मच्छरजनित रोगों से बचाव के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। साथ



ही अभियान के दौरान किए जा रहे कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचारी रोगों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ अन्य विभागों की जिम्मेदारियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नालियों की सफाई, ड्राइयों की कटाई, जलभराव का निस्तारण, फोंगिंग और एंटी लार्वा दवाओं का नियमित छिड़काव सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जनजागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर विशेष जोर दिया गया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आशा,

अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि जनपदों में स्वच्छता अभियान को गति देते हुए नालियों की नियमित सफाई, जलभराव की रोकथाम, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा मच्छरजनित रोगों से बचाव के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही अभियान के दौरान किए जा रहे कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचारी रोगों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ अन्य विभागों की जिम्मेदारियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नालियों की सफाई, ड्राइयों की कटाई, जलभराव का निस्तारण, फोंगिंग और एंटी लार्वा दवाओं का नियमित छिड़काव सुनिश्चित किया जाए।

एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विभाग की टीमों के माध्यम से लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने स्वच्छता अपनाने, मच्छरों से बचाव के उपाय करने तथा रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। अमित कुमार घोष ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना

है। इसके लिए सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करना होगा। उन्होंने जिलों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अभियान की नियमित समीक्षा और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में विशेष सचिव रवि रंजन, धीरेन्द्र सचान, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि तथा अपर निदेशक भौतिक रूप से उपस्थित रहे, जबकि सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी वचुंअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

यूपी टी-20 मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों पर जमकर हुई धनवर्षा, कर्ण शर्मा बने सबसे महंगे खिलाड़ी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आगरा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) द्वारा आयोजित यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन की मिनी नीलामी में खिलाड़ियों पर जमकर धनवर्षा हुई। आगरा के ताज कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नीलामी में 250 से अधिक खिलाड़ियों पर बोली लगी। अनुभवी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और आईपीएल स्टार कर्ण शर्मा इस नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। पांच लाख रुपये के बेस प्राइस वाले मेरठ के कर्ण शर्मा को कानपुर सुपरस्टार्स ने 23 लाख रुपये में अपनी टीम से जोड़ा। नीलामी में दूसरी सबसे बड़ी बोली बुलंदशहर के तेज गेंदबाज शुभम गौतम पर लगी। मात्र 2.50 लाख रुपये के बेस प्राइस वाले शुभम को नोएडा किंग्स ने 21.50 लाख रुपये में खरीदा। यूपीसीए के स्पॉट भी दिए। बैठक में विशेष सचिव रवि रंजन, धीरेन्द्र सचान, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि तथा अपर निदेशक भौतिक रूप से उपस्थित रहे, जबकि सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी वचुंअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।



भी फ्रेंचाइजी ने बड़ा दान खेला। दोनों खिलाड़ियों को 17.50-17.50 लाख रुपये में खरीदा गया। मोहम्मद शारिम काशी रुद्रास जबकि शिवा सिंह नोएडा किंग्स का हिस्सा बने। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की गरिमामयी मौजूदगी में आयोजित इस मिनी नीलामी का संचालन सुप्रसिद्ध ऑक्शनर अंगद बेदी ने किया। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने युवा खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने और उन्हें अगले स्तर तक पहुँचाने में मदद करने के लिए अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं मेरठ के बल्लेबाज शिवम चौधरी को गौर गोरखपुर लायंस ने 21 लाख रुपये में खरीदा। इसके अलावा मोहम्मद शारिम और शिवा सिंह पर

दिखाई दे रहा है। यूपी टी-20 लीग की गवर्निंग कारिसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा कि यूपी टी-20 लीग हमारे लिए कभी सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रही। शुरुआत से ही हमारा उद्देश्य उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली क्रिकेटर्स के लिए अवसर पैदा करना और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का मंच देना रहा है। उन्होंने बताया कि नीलामी में लखनऊ फाल्कंस ने समीर चौधरी को 11.75 लाख रुपये में खरीदा, जबकि नोएडा किंग्स ने शोएब सिद्दीकी को 11.25 लाख रुपये में अपनी टीम का हिस्सा बनाया। कानपुर सुपरस्टार्स ने यशोवर्धन सिंह व प्रियांशु पाण्डेय को 6.60 लाख रुपये में खरीदा। वहीं काशी रुद्रास ने विजय यादव को 5.20 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा, जबकि नोएडा किंग्स ने अंचित यादव को उनके बेस प्राइस पांच लाख रुपये में खरीदा। मेरठ मावेरिक्स ने करण चौधरी और कुणाल यादव को पांच-पांच लाख रुपये में अनुबंधित किया।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 48वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 48वां स्थापना दिवस शनिवार को लखनऊ के यूथ हॉस्टल क्लब में धूमधाम से मनाया गया। समारोह के दौरान एसोसिएशन के प्रदेश, मंडल एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों का मनोनयन भी किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन की स्थापना 25 जुलाई 1978 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तब से संगठन देशभर में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों और संस्थानों के हितों की रक्षा तथा उनके अधिकारों के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा 21 जून 2011 को जारी आदेश का भी उल्लेख किया गया। संगठन का दावा है कि वह समय-समय पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के



हित में आंदोलन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहा है तथा चिकित्सकों की समस्याओं के समाधान के लिए लघुतम प्रयासरत है। एसोसिएशन के सचिव मिथिलेश कुमार मिश्रा ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं शुभचिंतकों से

अधिक से अधिक संख्या में संगठन की सदस्यता ग्रहण कर इसे मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन भविष्य में भी चिकित्सकों के हितों की रक्षा और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां। बिसवां नगर के प्रतिष्ठित एल्लिप्स ग्लोबल स्कूल में विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, टीम भावना एवं प्रबंधन कौशल विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न कक्षाओं से चयनित विद्यार्थियों के हाउस कैबिनेट का गठन किया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को जिम्मेदारी, निर्णय लेने की क्षमता तथा सामूहिक नेतृत्व का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना रहा। कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 के छात्र राघव भल्ला को हेड बॉय तथा छात्रा रुसदा फुरकान को हेड गर्ल नियुक्त किया गया। इनके साथ विभिन्न हाउसों के कैप्टन एवं अन्य पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं। येलो हाउस (एंटप्राइज) की कैप्टन हिबा अंसारी के साथ शौर्य वर्मा, अमृता वर्मा, प्रांजल शर्मा एवं वैवस्वत मिश्र को नियुक्त किया गया। ग्रीन हाउस (एवोल्यूशन) की कैप्टन समृद्धि वैश्य के



साथ सत्यप्रकाश, गुरमिसरन कौर, स्वप्निल शर्मा, प्रिया भल्ला एवं शिवा शुक्ल को जिम्मेदारी दी गई। रेड हाउस (एंड्यूरेंस) की कैप्टन वैशाली जैन के साथ अभिनव पटेल, मांसी वर्मा, मो. उमैद, मान्या त्रिपाठी एवं शीर्ष त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। वहीं ब्लू हाउस (एंडेवर) की कैप्टन हर्षिता सिंह के साथ रामांश कुमार, शानू विश्वकर्मा, सरश भदौरिया, अनुकृष्णा सिद्धार्थ शौर्य एवं दीप श्रीवास्तव को हाउस गतिविधियों की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर विद्यालय डायरेक्टर उमंग राजवंशी तथा विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती दीपा चंद्रा उपस्थित रहीं। उन्होंने नव-नियुक्त छात्र पदाधिकारियों को शुभकामनाएं

देते हुए कहा कि विद्यालय में हाउस प्रणाली विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, सहयोग की भावना, जिम्मेदारी निभाने की क्षमता एवं प्रभावी प्रबंधन कौशल का विकास होता है। विद्यालय प्रबंधक श्री उमंग राजवंशी ने कहा कि छात्र पदाधिकारी विद्यालय की विश्वकर्मा, सरश भदौरिया, अनुकृष्णा सिद्धार्थ शौर्य एवं दीप श्रीवास्तव को हाउस गतिविधियों की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर विद्यालय डायरेक्टर उमंग राजवंशी तथा विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती दीपा चंद्रा उपस्थित रहीं। उन्होंने नव-नियुक्त छात्र पदाधिकारियों को शुभकामनाएं

चंद्रा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नेतृत्व केवल पद प्राप्त करने का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने, दूसरों का मार्गदर्शन करने और अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करने का नाम है। उन्होंने सभी नव-नियुक्त पदाधिकारियों से ईमानदारी, अनुशासन एवं समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का वातावरण उत्साह, ऊर्जा एवं गौरव से परिपूर्ण रहा। नव-नियुक्त छात्र पदाधिकारियों ने विद्यालय की गरिमा एवं हाउस भावना को बनाए रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संकल्प लिया।

संक्षिप्त खबरें

हर बच्चे तक न्याय पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

लखनऊ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा लागू 'चाइल्ड-फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रेन स्कीम-2024' के तहत बच्चों को निःशुल्क, सुरक्षित, सुलभ और बाल-अनुकूल विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), लखनऊ ने कहा है कि प्रत्येक बच्चे को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना समाज और व्यवस्था की साझा जिम्मेदारी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के प्रभारी सचिव जीवक कुमार सिंह ने बताया कि यह योजना 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए लागू है। इसके अंतर्गत विधि का उल्लंघन करने वाले बालक, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, बाल श्रमिक, मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, लैंगिक हिंसा, बाल विवाह, दिव्यांग, अनाथ, परित्यक्त, गुमशुदा तथा अन्य संवेदनशील परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

मानसिक रोग एवं बौद्धिक अक्षमता से पीड़ितों को मिलेगी निःशुल्क विधिक सहायता

लखनऊ। मानसिक रोग एवं बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित व्यक्तियों को न्याय तक सहज और प्रभावी पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने 'लीगल सर्विसेज टू पर्सन्स विद मेंटल इलनेस एंड पर्सन्स विद इंटेल्लेचुअल डिसेम्बिलिटी स्कीम-2024' लागू की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), लखनऊ ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को पूरी तरह निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के प्रभारी सचिव जीवक कुमार सिंह ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य मानसिक रोग अथवा बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन, समान अवसर तथा न्याय तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है।

नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर में हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में सौपा गया ज्ञापन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां सीतापुर। नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर में हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के बिसवां विधानसभा क्षेत्र में दिग्विजय सिंह देव और सेजता विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू के नेतृत्व में अलग-अलग महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी राहुल सिंह को सौपा और केंद्र और अलग-अलग प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारे बाजी की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दिग्विजय सिंह देव के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन कार्यक्रम गुलजार शाह साह से शुरू हुआ सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धर्मद प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो जौहर विश्वविद्यालय नहीं गिरने देगे अखिलेश यादव जिनबाद मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी इत्यादि के नारे लगाते हुए बड़े चैनोहरे होते हुए तहसील पहुंचे और वहां जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौपा।



ज्ञापन में मांग की गई कि डीजल पेट्रोल के दाम कम किये जाए स्मार्ट मीटरों को बिना उपभोक्ताओं की जानकारी के भार ना बढ़ाया जाए पेपर लीक की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए निर्माण अधीन एवं जर्जर सड़कों को तत्काल दुरुस्त कराया जाए। तहसील क्षेत्र पंचायत और नगर पालिका विद्युत विभाग एवं अन्य सरकारी विभागों में पनप रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवन ध्वस्तीकरण का आदेश वापस

लिया जाए। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री कमलेश यादव, ब्लाक प्रमुख शांति यादव, समाजवादी पार्टी के नेता प्रमोद वर्मा, सपा नेता अफजाल कौसर, शम्बीर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए निर्माण अधीन एवं जर्जर सड़कों को तत्काल दुरुस्त कराया जाए। तहसील क्षेत्र पंचायत और नगर पालिका विद्युत विभाग एवं अन्य सरकारी विभागों में पनप रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवन ध्वस्तीकरण का आदेश वापस

:- अति अल्पकालिक निविदा सूचना :-

क्र०सं०	वाहन किराये पर, वाहन का प्रकार	दर
1	वैननआर	
2	स्विफ्ट डिजायर	

(मनोज कुमार सागर)
फल संरक्षण अधिकारी
लखनऊ

:- अति अल्पकालिक निविदा सूचना :-

क्र०सं०	सामग्री एवं कार्य का नाम	दर
1	1-रजिस्टर 1 क्वार, 2-रजिस्टर 2 क्वार, 3-रजिस्टर 4 क्वार, 4-पेन स्टैण्ड 2 पेन, 5-पेन स्टैण्ड 4 पेन, 6-ए-4 पेपर, 7-पिन कुशन, 8-पेपर बेट, 9-स्कैल 12, 10-कल्कुलेटर, 11-गोद, 12-गम स्टिक, 13-आलपिन डिब्बी, 14-टैग, 15-आलपिन यू टाईप, 16-स्टैप्स पैड, 17-स्टेप्लर छोटा, 18-स्टेप्लर बड़ा, 19-पेन पायलट, 20-पेन नीला साधारण, 21-पेन लाल साधारण, 22-11-सी रजिस्टर, 23-पेन बी-5, 24-पेन बी-7, 25-रिसीट-बी डिस्पेंसर रजिस्टर, 26-कॉपी, 27-व्हाइटनर, 28-स्कैच पेन	

(मनोज कुमार सागर)
फल संरक्षण अधिकारी
लखनऊ

संपादकौय

छोटे परिवार, बड़े संकट

देश के बहुचर्चित 'हनीमून मर्डर' केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने आधुनिक जीवनशैली से पारिवारिक विच्छेदन पर जो गंभीर टिप्पणी की, मानो उसने भारतीय समाज की दुखती रग पर हाथ रख दिया। सोनम रघुवंशी मामले में मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ए.एम. सुरेन्द्र और न्यायमूर्ति पी.बी. वलले की बेंच ने गंभीर टिप्पणी की कि आज पति-पत्नी के रिश्तों में भरोसा कम हो रहा है। पहले संयुक्त परिवार रिश्तों को संभालते थे। संयुक्त परिवार ईसान को निराशा सहना और झड़पट करना सिखाते थे। लेकिन आज छोटे परिवारों की व्यवस्था के कारण पुरुषों व महिलाओं में डिप्रेशन बढ़ रहा है। लोग छोटी-छोटी बातों में चिढ़ने लगते हैं। गैजेट्स की लत ने इस संकट को और बढ़ाया है। जस्टिस सुरेन्द्र ने तो यहां तक कहा कि आज बच्चा किसी बड़े पति पर जरा रो दे, माता-पिता उसे मोबाइल थमा देते हैं। निस्संदेह, भवनाओं का विकल्प नहीं गैजेट्स नहीं हो सकते। धीरे-धीरे बच्चों को इस मोबाइल की लत लग जाती है। उनकी एकाग्रता भंग होने लगती है। भले ही अदालत के समक्ष एक संगीन अपराध का मामला था, लेकिन उसने उस गंभीर संकट के मर्म पर चोट की है, जिससे आप दिन पर दिन परिवार बिलखाव की दहलीज पर खड़े नजर आते हैं। विवादांश देखिए कि जिस भारतीय समाज में 'तलाक' के लिये कोई शब्द ही नहीं था, यहां अदालतों में रिश्तों को तोड़ने वालों की भीड़ बढ़ चुकी है। यहां तक कि एक बार अदालत को कहना पड़ा कि पारिवारिक झगड़ों के कारण महत्वपूर्ण कानूनी मामलों पर दबाव बढ़ रहा है। एक समय था कि पश्चिमी जगत में भारतीय परिवार संस्था की सार्थकता व समृद्ध परंपराओं की दुहाई दी जाती थी। लेकिन आज उसी भारत ने जिसकी समाज का अंधानुकरण करके एकल परिवार को जीवन का लक्ष्य बना लिया है। पश्चिम के चले लखों परिवार संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहे हैं। जिससे पारिवारिक संस्था संकटों से जूझ रही है। हाल के दिनों में विवाह से ठीक पहले और विवाह के ठीक बाद के, कई विभत्स हत्याकांड सामने आए हैं, जिन्होंने हर संवेदनशील व्यक्ति को झकड़ोया है। निर्मम हत्या करने वाली महिला के पति व मीतलों के पास प्रतीक्षा, अचल संतति व बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं थी। निस्संदेह, धन-संपदा व भारी चमक-दमक से जीवन का सुख नहीं खरीदा जा सकता। संत कबीरदास ने सदियों पहले कह दिया था कि... जब आप संतोष धन सब धन धूर पतन। पतन को तो तमाम परमियों व विलासिता के साधनों के बावजूद लोग खुश नहीं हैं। ऐसे में घातक कदम उठाने वाले महिलाओं व पुरुषों की परवरिश में भी कहीं न कहीं कोई कमी जरूर रह गई है। पहले साझे परिवारों में दादा-दादी या नाना-नानी, अपने जीवन के कठिन अनुभवों व पैसे-पुस्रसान से हासिल ज्ञान से बेटे-बेटियों व पोते-पोतियों को सीख देती थी। जीवन मूल्यों की कहानियां सुनाया करते थे। संयुक्त परिवार में दादा-पिता को किसी अप्रत्याशित झटके झेलने वाला सुसुरा कवच माना जाता था। सुख-दुःख का मुकाबला साझे रूप में करने से वह कम महसूस होता था। घर की सुस्का बनी रहती थी। बूढ़ी मां भले ही शारीरिक रूप से अक्षम होती, लेकिन भरोसा बना रहता था कि घर में मां तो है। पिता तो हैं। अब जब पति-पत्नी असीमित इच्छाओं की पुष्टि के लिये काम पर चले जाते हैं तो घर किसके सहारे रहे? बच्चा किसके भरोसे रहे? कामवालों के? जो चंद पैसों के लिये घर में काम करने आते हैं। जो वहां आकर अपने घर के अभावों व दुख को सुनाना इस घर की समृद्धि से करती है। वहीं घर के बच्चे की देखभाल के साथ अपने संस्कार भी देती है। दरअसल, आज परिवार में रिश्तों से बड़े अहम 2 हो गए हैं। इगो का प्रदर्शन व अक्सर रिश्तों के बिखाव की वजह बनता है। कोई झुकने को तैयार नहीं होता है तो परिवार को टूटने से कौन रोकेगा? जाहिर है जो बात पति-पत्नी के बीच नहीं बनी, वो कोर्ट-कचहरी में क्या बनेगी? अलावाव का त्रास मनमुटाव से ज्यादा भयावह होता है। तभी तो अदालतों में तलाक की अर्जियां की संख्या दिन-दुगुनी और रात चौगुनी गति से बढ़ रही है।

जल संकट का असंतुलित प्रबंधन अस्तित्व पर मंडराता खतरा



जल केवल प्रकृति का उपहार नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का आधार है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जल के बिना असंभव है, फिर भी विरंडबा यह है कि जिस जल को हमारी संस्कृति ने देवत्व प्रदान किया, उसी जल के प्रति हमारा व्यवहार सबसे अधिक लापरवाह रहा है। आज देश और दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों में जल संकट प्रमुख बन चुका है। बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध भूजल दोहन, जलवायु परिवर्तन और वर्षाजल के समुचित प्रबंधन के अभाव ने इस संकट को भयावह बना दिया है। यदि समय रहते चेतना नहीं जागी तो आने वाले वर्षों में पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि सामाजिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और मानवीय संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। हाल के शोध इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर के अध्ययन के अनुसार पिछले दो दशकों में उत्तर भारत का भूजल भंडार लगभग 450 घन किलोमीटर घट चुका है। यह मात्रा देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक इंदिरा सागर का भी कुल जल संग्रहण क्षमता से लगभग 37 गुना अधिक है। यह आंकड़ा केवल वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि भविष्य के संकट का स्पष्ट संकेत है। इसका अर्थ है कि जिस भूजल पर करोड़ों किसानों की खेती और करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है, वह तेजी से समाप्त हो रहा है। इस भयावह स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। वर्ष 1951 से 2021 के बीच मानसूनी वर्षा में लगभग 8.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दूसरी ओर, उत्तर भारत में सर्दियों का तापमान भी बढ़ा है। तापमान में यह मामूली प्रतीत होने वाली वृद्धि भी मिट्टी की नमी को तेजी से कम करती है। परिणामस्वरूप खेती को पहले की अपेक्षा अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।

जब वर्षा कम होती है और सिंचाई की मांग बढ़ती है, तब किसान भूजल पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। यही कारण है कि भूजल का पुनर्भरण कम और दोहन अधिक हो रहा है। आज भारत के अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर हर वर्ष नीचे जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य भारत के कई हिस्से इस संकट की चपेट में हैं। अनेक स्थानों पर सैकड़ों फीट गहराई तक बोरेवल खोदने के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। कई गांवों में हैंडपंप सूख चुके हैं और शहरों में टैंकर संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। यह स्थिति बताती है कि यदि हमने अपनी जल नीति नहीं बदली तो आने वाले समय में पानी का संकट भोजन के संकट में भी बदल सकता है। भारत की कृषि व्यवस्था आज भी लगभग 80 प्रतिशत मीटे जल का उपयोग करती है। दुर्भाग्य से धान, गन्ना जैसी अधिक पानी वाली फसलें उन क्षेत्रों में भी उगाई जा रही हैं जहां जल संसाधन सीमित हैं। मुफ्त बिजली और सस्ते पानी की नीतियों ने कई क्षेत्रों में अनियंत्रित भूजल दोहन को बढ़ावा दिया है। जल का मूल्य शून्य समझे जाने के कारण उसका संरक्षण भी नहीं हो पा रहा। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि नीति को जल उपलब्धता के अनुरूप बनाया जाए। जिन क्षेत्रों में पानी कम है, वहां मोटे अनाज, दालें, तिलहन

तथा कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल संकट केवल खेती तक सीमित नहीं है। उद्योगों, महानगरों और बढ़ते शहरी विस्तार ने भी भूजल पर अत्यधिक दबाव डाला है। बड़े-बड़े भवनों, कॉलोनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षाजल सिंधे नालों में बह जाता है। यदि प्रत्येक भवन में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो जाए तो लाखों लीटर पानी हर वर्ष धरती के भीतर पहुंच सकता है। दुर्भाग्यवश अनेक राज्यों में कानून तो बने, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं हो पाया। जल संकट का एक और गंभीर पक्ष जल प्रदूषण है। देश की अधिकांश नदियां औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक कचरे और सीवेज के कारण प्रदूषित हो चुकी हैं। जब नदियों में और तालाबों का जल उपयोग योग्य नहीं रहता तो भूजल पर दबाव और बढ़ जाता है। इसलिए जल संरक्षण के साथ-साथ जल स्रोतों की स्वच्छता भी समान रूप से आवश्यक है। नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पारिस्थितिकी का जीवनरेखा है। यदि नदियां स्वस्थ रहेंगी तो भूजल भी समृद्ध होगा। आज आवश्यकता केवल नई परियोजनाओं की नहीं, बल्कि जल संस्कृति के पुनर्जागरण की है। भारत में कभी तालाब, बावड़ियां, जोहड़, कुंड और पारंपरिक जल संचनाएं गांवों की पहचान

हाल के शोध इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर के अध्ययन के अनुसार पिछले दो दशकों में उर भारत का भूजल भंडार लगभग 450 घन किलोमीटर घट चुका है। यह मात्रा देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक इंदिरा सागर बांध की कुल जल संग्रहण क्षमता से लगभग 37 गुना अधिक है। यह आंकड़ा केवल वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि भविष्य के संकट का स्पष्ट संकेत है। इसका अर्थ है कि जिस भूजल पर करोड़ों किसानों की खेती और करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है, वह तेजी से समाप्त हो रहा है।

होती थीं। वे वर्षा के जल को रोककर भूजल को समृद्ध बनाती थीं। आधुनिक विकास की दौड़ में इन जल स्रोतों को या तो नष्ट कर दिया गया या अतिक्रमण का शिकार बना दिया गया। यदि इन पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्जीवन किया जाए तो जल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जल संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। घरों में पानी की आवश्यक बर्बादी रोकना, वर्षाजल संचयन अपनाना, रिसाव ठीक करना, कम पानी वाले उपकरणों का उपयोग करना और बच्चों में जल संरक्षण के संस्कार विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक परिवार प्रतिदिन कुछ लीटर पानी भी बचाए तो राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों लीटर जल की बचत संभव है। सरकार को भी जल प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। प्रत्येक जिले के लिए भूजल बजट तैयार किया जाए, भूजल दोहन पर वैज्ञानिक नियंत्रण हो, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों-ड्रिप और स्प्रिंकलर-को व्यापक प्रोत्साहन मिले तथा ऐसे कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए जो कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित करे। साथ ही जल शिक्षा को विद्यालयों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जल के महत्व को केवल

पुस्तकों में नहीं, व्यवहार में भी समझ सके। भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम हमारे पास आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल बचेगा? यदि आज भी हम जल को केवल उपभोग की वस्तु समझते हैं तो आने वाले वर्षों में जल के लिए संघर्ष पलायन और सामाजिक असंतोष बढ़ने का स्वाभाविक होगा। खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होगा, महंगाई बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट आएगा। इसलिए जल संरक्षण केवल पर्यावरण के विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक शांति का भी प्रश्न है। आज समय की पुकार है कि 'जल बचाना ही भविष्य बचाना है।' हमें बदलते जलवायु के अनुसंधान अपनी नीतियों, प्रणाली और जीवनशैली में व्यापक परिवर्तन लाने होंगे। वर्षा की प्रत्येक बूंद को धरती से उतारना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना और जल अनुशासन को जन-आंदोलन बनाना ही इस संकट का सबसे प्रभावशाली समाधान है। यदि सरकार, वैज्ञानिक, किसान, उद्योग, सामाजिक संगठन आम नागरिक मिलकर इस दिशा में संकल्पबद्ध प्रयास करें तो जल संकट का निवारण संभव है। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष करना मानव सभ्यता की सबसे बड़ी विवशता बन जाएगा।

पुस्तकों में नहीं, व्यवहार में भी समझ सके। भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हमारे पास आज वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल बचेगा? यदि आज भी हम जल को केवल उपभोगी की वस्तु समझते हैं, तो जल के लिए संघर्ष बढ़ेगा। जल को केवल उपभोगी की वस्तु समझना और वाले वर्षों में जल के लिए संघर्ष प्रलायन और सामाजिक असंतोष बढ़ाने का स्वाभाविक होगा। खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होगा, महंगाई बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट आएगा। इसलिए जल संरक्षण केवल पर्यावरण के विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक शांति का भी प्रश्न है। आज समय की चुनौती है कि 'जल वचन' ही भविष्य का पता है।' हमें बदलते जलवायु के अनुरूप अपनी नीतियों, प्रणाली और जीवनशैली में व्यापक परिवर्तन लाने होंगे। वर्षा की प्रत्येक बूंद को धरती तक उतारना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना और जल अशुशसन को जन-आंदोलन बनाना ही इस संकट का सबसे प्रभावी समाधान है। यदि सरकार, वैज्ञानिक, किसान, उद्योग, सामाजिक संगठन और आम नागरिक मिलकर इस दिशा में सकलबुद्धि प्रयास करें तो जल संकट का अवसर में बदला जा सकता है। अन्यथा वह जल दूर नहीं जा पाती की एक-एक बूंद के लिए सफ़र करना मानव सभ्यता की सबसे बड़ी विवशता बन जाएगा।

संवाद से सशक्त होगा लोकतंत्र, हिंसा से नहीं

दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद भवन तक हाल के मांडीोलन के दौरान जो तनाव, ठकुराव और हिंसक घटनाएँ देखने को मिलीं, वे केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ठकुराव, बैरिकेड तोड़ने के प्रयास, मेट्रो स्टेशन में जबरन प्रवेश की कोशिश, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग—ये सभी दृश्य उस लोकतांत्रिक संस्कृति के अनुरूप नहीं हैं जहाँ जा सकते, जिसकी आधारशिला अहिंसा, संवाद और संवैधानिक म्यादाओं पर रखी गई है। भारत आज आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 की ओर बढ़ रहा है। यह केवल आर्थिक महाशक्ति बनने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के परिपक्वता की कसौटी पर भी स्वयं को सिद्ध करने का अवसर है। यदि हम आज भी असहमति को हिंसा, ठकुराव और अराजकता के माध्यम से व्यक्त करेंगे, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होगी। लोकतंत्र की शक्ति सड़क पर शक्ति-प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विचारों की शक्ति, संवाद की संस्कृति और संवैधानिक क्रियाओं में निहित होती है। राहुल गांधी द्वारा नीट पर लीक प्रकरण को लेकर चल रहे घटना-प्रदर्शन के दौरान अचानक अपने सहयोगी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के निकट घुसने पर बैठना और संसद की अजय सड़क को राजनीतिक संघर्ष का मंच बनाना अनेक गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जिस प्रकार इससे पहले काँकरोच जनता पार्टी के



तथाकथित छात्रों एवं कार्यकर्ताओं ने संसद चलो मार्च के दौरान तनावपूर्ण, अराजक एवं हिंसक माहौल बनाने की घटनाएं सामने आईं, उससे यह आशंका बलवती हुई कि कुछ राजनीतिक शक्तियां भारत में भी नेपाल जैसे अराजक परिस्थितियों पैदा करने को उजावले हैं। सरकार की संस्कृता और सुरक्षा एजेंसियों की समय रहते की गई कार्रवाई से, कुछ कमियों के बावजूद, इस बड़े संकट को टाल दिया गया, अन्यथा दिल्ली लंबे समय तक हिंसा और आशांति की संघर्ष भरी आ सकती थी। देश पहले भी नागरिका संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के दौरान शाहीन बाग में लाभग सी दिनों तक एक प्रमुख सड़क के अवरुद्ध रहने और उससे आम नागरिकों को हुई भारी कठिनाइयों का अनुभव कर चुका है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार निर्विवाद है, लेकिन उसका स्थान संसद, संवाद और संवैधानिक संस्थाएं हैं, न कि सड़क पर

टकराव और अराजकता। विपक्ष यदि बार-बार ऐसे आंदोलनों को प्रोत्साहित करता है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि उसका उद्देश्य लोकतांत्रिक विमर्श को मजबूत करना है या राजनीतिक ध्रुवीकरण और अस्थिरता को बढ़ावा देना। जनता अपेक्षा करती है कि सभी दल संसद को सर्वोच्च मंच मानते हुए विलंब जवाबदेही अनुचित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक के अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण त्र सभा करने का अधिकार देता है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। किंतु अधिकार के साथ कर्तव्य और मर्यादा भी हैं। प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, पर्यवर्जनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, टकराव करना, हिंसा फैलाना अथवा आम के जीवन को बाधित करना किसी भी लोकतांत्रिक आचरण नहीं कहा जा सकता। लन अपनी नैतिक शक्ति खो देता है, तो भी समाज की सहानुभूति को बेटौती है। नानी भी सत्य है कि लोकतंत्र केवल जनता नहीं, बल्कि सरकार के लिए भी च का नाम है। सरकार को भी आंदोलनों का नून-व्यवस्था की समस्या मानकर नहीं र्हािए। जब भी किसी वर्ग, विशेषकर छात्रों में असंतोष उत्पन्न हो, तो उसका

समय रहते समाधान खोजने का प्रयास होना चाहिए। संवाद के दरवाजे जितनी जल्दी खुलेंगे, टकराव की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी। लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य, संवेदनशीलता और संवाद की इच्छा होती है। इतिहास साक्षी है कि भारत के अधिकांश सफल जनआंदोलन अहिंसा और संवाद की शक्ति से ही सफल हुए हैं। महात्मा गांधी ने विश्व को यह संदेश दिया कि सत्य और अहिंसा सबसे बड़े अस्त्र हैं। वर्ष 2011 का अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी इसका उदाहरण है। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन आंदोलन का नैतिक बल उसकी शांति और अनुशासन में था। उसी कारण सरकार को संवाद का पस्ता अपनाना पड़ा और पूरे देश में एक सकारात्मक बहस प्रारंभ हुई। इसके विपरीत जहां-जहां आंदोलनों ने हिंसा का मार्ग अपनाया, वहां उनका मूल उद्देश्य पीछे छूट गया और चर्चा केवल हिंसा तक सीमित होकर रह गई। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी कौन-सी शक्तियाँ हैं, जो सामान्य और भोली-भाली जनता एवं देश के युवाओं को हिंसा की ओर धकेल देती हैं? कौन-से तत्व आंदोलनों की दिशा बदलकर उन्हें अराजकता में परिवर्तित कर देते हैं? यह चिंता केवल सरकार की नहीं, पूरे समाज की होनी चाहिए। लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन यदि असहमति के मंच पर राष्ट्रीयवादही, अराजक अथवा हिंसक तत्व सक्रिय हो जाएं, तो उन्हें नियंत्रित करना भी

लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनिवार्य दायित्व बन जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ अराजकता की स्वतंत्रता नहीं हो सकता। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। जंतर-मंतर लोकतांत्रिक विरोध का प्रतीक स्थल है। यदि इन दोनों के बीच हिंसा, तोड़फोड़ ज़रूर अराजकता का दृश्य निर्मित होता है, तो यह केवल राजधानी की घटना नहीं रहती, बल्कि पूरे देश और विश्व के समाने भारतीय लोकतंत्र की छवि को प्रभावित करती है। लोकतंत्र की गरिमा इस बात में नहीं कि कौन अधिक आक्रामक है, बल्कि इस बात में है कि कौन अधिक संयमित और उत्तरदायी है। राजनीतिक दलों को भी अल्पमंथन करना होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के दो पहिए हैं। यदि दोनों के बीच संवाद समाप्त हो जाएगा, तो लोकतंत्र टकराकर का अखाड़ा बन जाएगा। विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, बल्कि रचनात्मक विकल्प प्रस्तुत करना भी है। उसी प्रकार सरकार का दायित्व केवल शक्ति प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि असहमति को सम्मानपूर्वक सुनना भी है। लोकतंत्र में किसी की पूर्ण विजय या पूर्ण पराजय नहीं होती, यदि अंततः संपाद, सहमति और समाधान ही सबसे बड़ी जीत होती है। छात्रों और युवाओं की समस्याओं का समाधान भी अंततः आवश्यक है। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा हैं। यदि उनकी आशाओं और अपेक्षाओं की उपेक्षा होगी, तो असंतोष स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह

युवाओं से नियमित संवाद स्थापित करे, उनके समस्याओं को समयबद्ध ढंग से सुने और समाधान को दिशा में ठोस कदम उठाए। वहीं युवाओं को भी यह समझना होगा कि हिंसा उनके आंदोलन का सबसे बड़ी शत्रु है। पथर और लाठी किसी समस्या का समाधान नहीं करते, वे केवल संवाद के पुल को तोड़ते हैं। आज आवश्यकता लोकतंत्र का अधिक परिपक्व बनाने की है। हमें ऐसी राजनीति से संस्कृति विकसित करनी होगी जिसमें विरोध भी लोकतंत्र के वैमनस्य न हो। मण्डपे हों, लेकिन मण्डपे न हों। संघर्ष हो, लेकिन हिंसा न हो। लोकतंत्र में बहस जितनी प्रखर होगी, राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। किंतु बहस का स्थान यह हिंसा ले लेगी, तो लोकतंत्र की आत्मा आहत होगी। जंतर-मंतर से संसद तक जो कुछ हुआ, उसे लोकतांत्रिक आदर्श नहीं कहा जा सकता। यह किसी परिपक्व राजनीतिक सोच का भी परिचायक नहीं है। राष्ट्र निर्माण का मार्ग टकराव नहीं, सहयोग है। हिंसा नहीं, समझति है। उग्रता नहीं, उदारता है। इसलिए आवश्यक है कि सभी पक्ष अनपने-अपने आग्रहों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। आज देश का ऐसे नेतृत्व और ऐसी जनचेतना की आवश्यकता है जो संवाद को संघर्ष से ऊपर रखे। सरकार उदारता और संवेदशीलता दिखाए, आंदोलनकारी संयम और अनुशासन अपनाएं तथा राजनीतिक दलों अल्पकालिक लाभ के बजाय लोकतंत्र को दीर्घकालिक मजबूती को प्राथमिकता दें।



मेघ- मेघ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपेक्षा से अधिक परिश्रम कराने वाला रह सकता है। कार्यों को पूरा करने में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, जबकि परिणाम उम्मीद से कुछ कम मिल सकते हैं। सामाजिक और प्रोपोकरी कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है, जिससे सम्मान भी मिलेगा।

वृषभ-वृषभ राशि के लोगों के लिए आज व्यापार और कार्यक्षेत्र में गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों के सहयोग से रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्रों में मेहनत के बाद सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक पक्ष पहले की तुलना में बेहतर रहेगा।

मिथुन-मिथुन राशि के जातकों का आज कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनकी पहले से कल्पना नहीं की गई थी। कार्यस्थल पर संयम और समझदारी से काम लेना लाभदायक रहेगा। नए लोगों पर तुरंत भरोसा करने से बचें और हर निर्णय सोच-समझकर लें।

कर्क-कक राशि के लिए आज का दिन अध्ययन और ज्ञान से जुड़े कार्यों में व्यावहारिक सोच अपनाने का संकेत

दे रहा है। विद्यार्थियों को व्यवहारिक विषयों में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार में साहसिक निर्णय लाभ पहुंचा सकते हैं। यदि यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए टालना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।

सिंह-सिंह राशि के जातकों के लिए आज प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। लंबे से अटके हुए कार्य पूरे होने से राहत मिलेगी और कलाभ की संभावना भी बन सकती है। नए लोगों के प्रभाव में लाभदायक साबित हो सकता है।

कन्या-कन्या राशि के लोगों का अधिकांश समय पारिवारिक और शुभ कार्यों में व्यतीत हो सकता है। सामाजिक और जनहित से जुड़े कार्यों में सक्रियता आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा।

तुला-तुला राशि के जात्रकों के लिए आज वास्तविक परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना अधिक लाभदायक रहेगा। कल्पनाओं के बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना से सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। अपनी प्रतिभा और अनुभव का सही उपयोग करें। किसी भ्रम या असमंजस में निर्णय लेने से बचें।

वृश्चिक-वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज सरकारी कार्यों और व्यवसाय से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य भी उचित प्रयासों से आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा।

कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति सफलता दिला सकती है।

धनु-धनु राशि के जाकों का आज नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाए रखना उचित रहेगा। भावनात्मक संबंधों से सहयोग और मानसिक संतुलन मिलेगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने का अवसरकता होगी, अन्यथा बजट प्रभावित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य सामान्य रह सके है, लेकिन थकान महसूस होने की संभावना रहेगी।

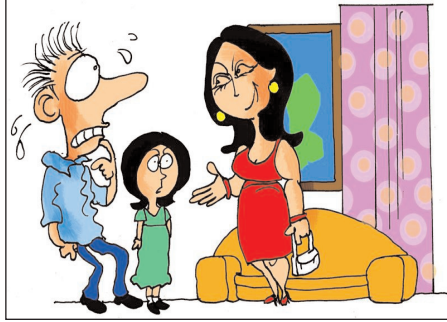
मकर-मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन उद्योग और तकनीकी कार्यों से जुड़े क्षेत्रों में लाभ दे सकता है। वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे महत्वपूर्ण कार्य आसानी से पूरे होंगे। नए संभव भविष्य में उपयोगी साबित हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

कुम्भ-कुम्भ राशि के जातकों के लिए आज कार्यक्षमता बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होगी। जिम्मेदारियाँ अधिक रहने से व्यस्तता बनी रहेगी। नई योजनाओं और नीतियों को लागू पर काम करने का अवसर मिल सकता है। संतान से जुड़े विषयों पर किसी विषय को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन धर्म से स्थिति संभल जाएगी। आर्थिक मामलों में संतुलित निर्णय लाभदायक रहेंगे।

मीन-मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुष्टि देने वाला हो सकता है। पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में दिखा देगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी।

न्याय नहीं, प्रतिशोध का माध्यम बनते कार्यस्थल

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों के एक चिंताजनक पक्ष पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति बी. बी. नागरला एवं न्यायमूर्ति अर. महादेवन की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वैवाहिक विवादों के दौरान पति या पत्नी द्वारा एक-दूसरे के नियोजता अथवा वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत-पत्र भेजने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी शिकायतों के परिणामस्वरूप कई बार संबंधित व्यक्ति की नौकरी चली जाती है या उसका सेवा-जीवन गंभीर रूप से प्रभावित होता है। न्यायालय के अनुसार, तलाक का मुकदमा लड़ना एक अलग बात है, किंतु किसी व्यक्ति की आजीविका और पेंशनवर प्रतिष्ठ को संकट में डाल देना कहीं अधिक गंभीर है। यदि किसी व्यक्ति की नौकरी गंभीर भाव हो जाए, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव भरण-पोषण (मैंटेनेंस) जैसे वैधानिक दायित्वों पर भी पड़ सकता है। पिछले पांच दशकों में विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक विवादों पर यह स्पष्ट किया है कि वैवाहिक विवादों के दौरान पति या पत्नी द्वारा एक-



दूसरे के नियोजता अथवा वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपमानित अथवा मानहानिकार शिकायतें करना केवल व्यक्तित्व प्रतीक्षा का माध्यम नहीं है, बल्कि इससे संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सेवा-जीवन और आजीविका पर भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। न्यायालयों ने समय-समय पर ऐसे आवरण को मानसिक क्रूरता के दृष्टिकोण से परखा है तथा परिस्थितियों के अनुसार इसे वैवाहिक संबंध-विच्छेद का आधार भी माना है। इस संबंध में सबसे प्रारंभिक और उल्लेखनीय निर्णयों में एक 'शकुन्ता कुमारी बनाम ओम प्रकाश घई' (दिल्ली उच्च न्यायालय, लिए यह कहना पर्याप्त था कि उसे भरण पोषण नहीं मिल रहा है। इसके लिए पर्याप्त तथ्य तब तक उसके परिवार के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय इस प्रकार की शिकायतों के प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'नियोजता के समक्ष इस प्रकार की असत्य शिकायतें करने से निस्संदेह मानसिक क्रूरता है। इससे कर्मचारियों की अपने नियोजता की दृष्टि में प्रतिष्ठा धूमिल होती है तथा उसके सेवा-जीवन और पदोन्नति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।' स्वभाविक रूप से इसका उद्देश्य है गंवा भाविक पड़ता है और उसकी मानसिक शांति भंग होती है।'

1980) का है। इस मामले में अलग रह रही पत्नी लोकसभा सचिवालय, जहाँ उसका प्रतिकार्यरत था, उस प्रालिखक उस पद दुर्व्यवहार तथा अन्य गंभीर आरोप लगाए। न्यायालय पाया कि यदि पत्नी वरुद्ध ईश्वर केवल भरपूर-पोषण प्राप्त करना था, तो उसका ना पर्याप्त था कि उसे भरपूर मिल रहा है। इसके लिए पत्नी वरुद्ध के विरुद्ध गंभीर आरोप प्रस्तुत नहीं थल। न्यायालय की शिकायतों के प्रभाव पर हुए कहा, 'नियोन्ता के समान' असत्य शिकायत करके सिक्त कूरता है। इससे कर्मचारी नियोन्ता की दुष्टि में प्रतिकार्य तथा उसके सेवा-जीवन और संभालनाओं पर प्रतिकूर है। स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव शक्ति पड़ता है। और शक्ति भंग होती है।'

